संवाद

पत्रकारिता, जनसंचार एवं नवमीडिया स्कूल, केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला

अप्रैल-मई, 2016

चेतना से संवेदना तक

http://de-layer.blogspot.in/p/sanvad-e-paper.html

गरीबों की सब्सिडी पर कैंची P-2

नशे की बढ़ती लत से युवाओं का भविष्य ख़तरे में

नरेन्द्र शर्मा

समाज के बदलते परिवेश में कुछ अलग करने की कामना, मानसिक तनाव और बहुत से शौक़ ऐसे कारण है जो नशे के प्रचलन को बढ़ा रहे हैं। इसका शिकार हमारी युवा पीढ़ी हो रही है। नशा करना युवाओं के लिए एक फैशन की तरह है जो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि भारत में चार लाख लोग कई तरह के नशे करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में दो लाख से ज्यादा लोग नशा करने की वज़ह से मर जाते है। बेरोज़गारी भी नशे का बहुत बड़ा कारण है। इतनी ज्यादा जनसँख्या होने के कारण भारत में बेरोज़गार युवा निराश होकर नशा करने लग जाते है जिसके कारण वह अपने घरों से पैसे चुराकर भी नशा करते है। इससे उन युवाओं के परिवारो को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

नशा कारोबार में नशीली दवाइयों का बढ़ता प्रभाव। साभार- pintrust.com

व्यापारी नशीले पदार्थ बेचते हैं और इन मासूमों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते है। परिणामस्वरुप नशे की लत में डूबे हुए लोगों के परिवारों को बहुत कुछ खोना पडता है। साथ ही साथ देश का भी नुकसान होता है। जिस वक़्त युवाओं की पढ़ने की उम्र होती है, वह नशे की वज़ह से अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे होते हैं। नशा एक लत के साथ-साथ व्यापार का केन्द्र भी बनता जा रहा है। नशे की रोकथाम के प्रति सरकार का लापरवाह रवैया इसके चलन को बढ़ा रहा है।

शराब की बोतल और सिगरेट की ड़िब्बी पर एक तरफ़ दी गई छोटी सी चेतावनी-"शराब या सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है" सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गई है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सरकार को इससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। नशे के प्रति लोगों को जागरुक करना पड़ेगा, जिससे लोग इसे इस्तेमाल न करें। इस पर रोक लगने के बाद ही भारत आगे बढ़ पाएगा।

सवालों के घेरे में मीडिया

सुरिन्द्र ठाकुर

मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है वर्तमान में अपने साथ जुड़ रहे दो शब्दों 'इंटरनेट' और 'इंडस्ट्री' को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ा है। हालिया मीडिया की कार्यशैली एवं घटनाओं के अवलोकन में आ रही मीडिया की भूमिका इसे सवालों की तरफ ले जा रही है। सवाल यह है कि क्या मीडिया सामाजिक विकास का माध्यम न रहकर एक स्वतंत्र उद्योग बनता जा रहा है?

समाज़ में मीडिया मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। यह समाज और सरकार के मध्य सवांद स्थापित करता है। समाज में हो रही विभिन्न घटनाओं को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने का कार्य मीडिया द्वारा किया जाता है। इसलिए मीडिया को समाज का आईना भी कहा जाता है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके कवरेज को लेकर मीडिया आरोपों से घिरा हुआ है। हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एक शोध छात्र द्वारा की गई आत्महत्या,जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में छात्रों पर देशद्रोह का आरोप, जाधवपुर विश्वविद्यालय,उस्मानिया विश्वविद्यालय और फिल्म एवं टेलिविजन इंस्टीटयूट पुणे में हुई घटनाओं को मीडिया द्वारा प्रस्तुत करने की शैली पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं।

भारतीय लोकतन्त्र के तीनों प्रारुपों सामाजिक,आर्थिक और राजनितिक लोकतन्त्र के विकास में मीडिया का योगदान सराहनीय है। सामाजिक विकास और जागरुकता जैसे उदेश्यों के साथ शुरु हुआ भारतीय मीडिया का सफ़र कैसे एक उद्योग बनने की दिशा में मुड़ गया है। इसका एक मुख्य कारण 1990 के बाद उदारीकरण,भूमण्डलीकरण और निजीकरण का दौर भी माना जा सकता है। जिसमें अर्थव्यवस्था का स्वरुप बाज़ार आधारित हो गया। पूंजीवाद के इस बढ़ते विचार ने मीडिया को अपनी तरफ आकर्षित किया। और मीडिया का सम्बन्ध बाज़ार से स्थापित हो गया।

अब दर्शकों को एक उपभोक्ता माना जाने लगा है। पब्लिक ब्राडकास्टिंग की रणनीति के भीतर भी संस्कृति और सामाजिक विकास के नाम मात्र संकेत मिल जाएगें। फिर निजी मीडिया कैसे मुखौटे से अछूता रह सकता है। मीडिया का यह कारोबारी चेहरा कोई नई बात नही है। मीडिया के कटेंट को उत्पाद का रुप दिया जा रहा है। इसकेबावजूद यह भी आशा की जा रही है कि यह चौथे स्तम्भ की छवि बनाए रखे।

बाजार आधारित व्यवस्था में फलते मीडिया ने अपने को बाजार पर आधारित बना लिया है। तमाम घरानों के बीच बाज़ार में बने रहने की प्रतिस्पर्धा और आगे रहने की होड़ में खबरों की यथार्थता खो रही है। जिसके परिणामस्वरुप मीडिया व्यवसायिक सफलता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले साधन से ज्यादा कुछ भी नही रहा है। इस बदलते परिवेश में मीडिया बिजनेस घरानों और राजनीतिक तबकों के बीच स्थापित होने वाले अन्तरसबधों ने मीडिया के मौलिक रुप को परावर्तित कर दिया है। अब ख़बर "क्या है" से ज्यादा "क्या हो" पर ज़ोर दिया जा रहा है।

कर्ज में डूबता देश

नितिश पोजटा

2007 के आसपास भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी। जिस वजह से बैंकों की स्थिति भी बेहतर हो गयी थी और बैंकों से कर्ज लेना भी आसान था। मगर वर्तमान में जब बैंकों के मुनाफे में भारी गिरावट दिख रही है। हालांकि यह तो एक शुरुआत है, क्योंकि जो गिरावट देखने को मिली, वह मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी और आखिरी तिमाही में कहीं ज्यादा हो सकती है। इसकी वज़ह यह भी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को कॉर्पोरेट जगत से पैसा वापस नहीं मिल रहा, और उनके कर्ज बट्टे खाते में जा रहे है।

कर व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद-जीएसटी

अंजना देवी

पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार किए जाने की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वस्तु एंव सेवा कर यानि जी.एस.टी विधेयक ससंद में पेश किया गया। इस विधेयक के पारित होने से विदेशी निवेश आकर्षित होगा। विशेषज्ञों की माने तो ऐसी कर प्रणाली लाने से सरकार को कर लेने में आसानी होगी तथा इससे कर व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी

इस नई कर प्रणाली से अर्थव्यवस्था में बदलाव की आशा की जा सकती है और यह आम आदमी की आर्थिक जटिलताओं को भी दूर करने में सक्षम हो सकती है क्योंकि इससे वस्तुओं के सस्ते होने की भी उम्मीद की जा रही है। केन्द्रीय वित्त मन्त्री अरुण जेटली का मानना है कि इस तरह की कर व्यवस्था लाने से उद्योगों ,सरकारों तथा उपभोक्ताओं सभी को फायदा होगा। इससे राज्यों में राजस्व वृद्धि तथा प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने के अवसर मिलेगें क्योंकि यह कर बिक्री के स्तर पर लगाया जाएगा तथा निर्माण लागत पर वसूला जाएगा। जहां इस कर प्रणाली के लागू होने से कई प्रकार के लाभों के बारे में बात की गई है वहीं कुछ आंशकाएं भी व्यापारी संगठनों द्वारा व्यक्त की जा रही है। इनमे एक यह भी है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने से उन्हें रिटर्न एक से बीस तारीख के बीच भरना पड़ेगा क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर ऑनलाइन भरने की अनिवार्यता की गई है। इसके आलावा ज्यादातर व्यापारी गांवों से है। अतः उन्हें इटंरनेट की जानकारी न होने से रिटर्न भरने में परेशानी होगी और भ्रष्टाचार का शिकार बनना पड़ सकता है।

कुछ व्यापारी संगठनों का मानना है कि उनके गांवों में बिजली न होने से उन्हे रिटर्न भरने में दिक्कत आएगी। अतः वे अपना रिटर्न कैसे भरेगें। साथ ही उन्हें सीए के पास रिटर्न भरने के लिए चक्कर लगाने पड़ेगे। ऐसी हालत में वे अपना व्यापार कब करेंगे। यदि सरकार इन समस्याओं को संज्ञान लेकर आगे बढ़े तो वस्तु एंव सेवा कर से देश की अर्थव्यवस्था व नागरिकों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है।

जहां खुदा एवं ईश्वर एक ही स्थान पर विराजमान है

राजेश कुमार

आज सारा ससांर धार्मिक उन्माद एंव धार्मिक कट्टरता में संलग्न है। वहीं पर ऐसी जगह है जहां खुदा एंव ईश्वर एक ही स्थान पर निवास करते है नाम है -खुदनेश्वर स्थान। यह जगह बिहार राज्य के समस्तीपुर जिलें से 15 कि0मी0दूर विद्यापति नगर के मोरवा नामक गाँव में स्थित है। इस मन्दिर के निर्माण के पीछे एक किवदंती है।

कहानी यह है कि एक मुस्लिम महिला जिसका नाम खुदनी बीवी था वह गाय चराया करती थी । एक दिन उसने देखा कि गाय एक जगह रुकी है तथा उसके थन से दूध की धारा बह रही है। फिर उसनें मन ही मन सोचा कि क्यूं न हम मिट्टी खोद कर देखे कि नीचे क्या है? खोदने पर यह पता चला कि नीचे एक शिवलिंग है। फिर उसने मुस्लिम होने के बावजूद वहां पूजा-अर्चना शुरकर दी। साथ ही वहां उसने एक झोपड़ी का निर्माण कराया और वहीं रहने लगी।

कुछ वर्षों के बाद उस महिला का देहान्त हो गया। चूंकि धर्म से वह मुस्लिम थी इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग वहां

खुदनेश्वर स्थान पर एक साथ नमाज एवं पूजा-अर्चना करते हुए लोग।
छायांकन- राजेश कुमार

मजार बनवाना चाहते थे। लेकिन वहां शिवलिंग था तो हिन्दू समाज के लोग वहां मन्दिर बनवाना चाहते थे। अन्त में दोनों समुदायों ने यह निर्णय लिया कि क्यूं न यहां एक मन्दिर का निर्माण कराया जाए तथा शिवलिंग और मजार की पूजा साथ में की जाए। यह बात दोनों धर्मों के लोगों ने मान ली और मन्दिर का निर्माण करवाया गया ***शेष खबर पृष्ठ दो पर*** .....

विज्ञापनों में महिलाओं का अभद्र निरुपण

ऋषिका शर्मा

विपणन प्रणाली में विज्ञापन एक प्रभावशाली माध्यम है। विज्ञापन संचार का एक साधन है। जिसका उद्देश्य उन लोगों के व्यवहार तथा राय को प्रभावित करना होता है। यह एक अभिव्यक्ति है जिसका इरादा उत्पाद को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ता पर प्रभाव डालना होता है।

विज्ञापनों में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी उत्पाद के विज्ञापन के लिए महिलाओं का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। टेलीविजन विज्ञापनों में महिलाओं को प्रोत्साहन के हथियार के रुप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि विज्ञापन जिस उत्पाद को लेकर है, उस उत्पाद का महिला से कोई लेना-देना नहीं होता है। अतः इन सब चीजों के कारण महिला भी केवल एक उत्पाद तथा लोगों को आकर्षित करने का सामान बन कर रह गयी है। जैसे कि पुरुषों की क्रीम का विज्ञापन है परन्तु उसमें विशेष भूमिका महिला की दिखाई जाती है।

विज्ञापनों में महिलाओं का रूढ़िबध्द चित्रण। *साभार- www.scoopwhoop.*

आज के दौर में हमें अक्सर यह देखने को मिलता है कि महिलाओं की हिस्सेदारी निरन्तर सौंदर्य-स्पर्धाओं में बढ़ती जा रही है। उसमें भाग लेना कोई गलत बात नही है, लेकिन उसके बाद महिलाओं का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है वह गलत है। आज अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ का विज्ञापन करना है तो प्रदर्शनी के तौर पर उसमे महिलाओं का इस्तेमाल करते है। चप्पल से लेकर कपड़ों तक हर एक चीज़ के विज्ञापन में महिलाओं को ही देखा जाता है।

इसका असर समाज़ पर भी पड़ रहा है क्योकिं जिस तरह से महिलाओं को प्रदर्शित किया जाता है उससे उनकी छवि पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

इसके लिए औरतों के अभद्र निरुपण को रोकने के कानून भी बनाया गया है, इस एक्ट के तहत यदि ऐसा कुछ किया जाता है तो दो साल की सज़ा तथा जुर्माना भरना पड़ सकता है लेकिन आज भी इसका चलन जारी है।

कॉरपोरेट जगत - एक तरफ छूट दूसरी तरफ़ लूट

नितिश पोजटा

देश में गरीबी आज भी उस स्तर पर है जहाँ किसी गरीब व्यक्ति या उसके परिवार को दिन भर काम करके भी एक समय का भोजन बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। भारत में गरीबों के लिए सब्सिडी एक ऐसा माध्यम है जिससे वे अपने परिवार का पेट पाल सकते है। चाहे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम हो या गैस सब्सिडी,गरीबो के लिए दो समय का खाना दोनों उपलब्ध कराता है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार देश की 65 प्रतिशत आबादी को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सब्सिडी दी जा रही है जिस पर लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जा रहे हैं। यह भी पहले के मुकाबले कम होता जा रहा है। वहीं गैस सब्सिडी को भी सरकार अनुचित मान रही है। हालांकि यह सच है कि इसका काफी हिस्सा ऐसे लोगों को जा रहा है जिन्हें इस सब्सिडी को न मिलने से फर्क नहीं पड़ता और उसे खत्म भी कर देना चाहिए।

सरकारें देश की जनता को यह बार-बार बताती हैं कि यदि देश को उन्नति की राह पर लाना है तो ऐसी योजनाओं को बन्द कर देना चाहिए। अगर गरीबों को वित्तीय मदद दी जाती है तो वह सब्सिडी कहलाती है, अगर अमीरों को कम दामों में ज़मीन, कर छूट व प्राकृतिक संपदाओं जैसी सौगातें दी जाती है तो वह विकास के लिए दिया वाला प्रोत्साहन कहलाता है। अमीरों तथा गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी को सरकारों ने जिस तरह से शब्दों की बेड़ी में बांधकर रखा है वह एक गरीब व्यक्ति की समझ से बाहर है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के

उचित मूल्य की दुकान से राशन लेती महिला। *छायांकन- नितिश पोजटा*

अनुसार 2004-05 से अब तक करीब 40 लाख करोड रूपए कर छूट के रूप में कोरपोरेट्स को दिए गए हैं। वहीं देश के एक राजनेता के अनुसार हर साल गैस सब्सिडी पर 45 हजार करोड रुपए खर्च किए गए जाते हैं जो एक साल की गरीबी मिटाने के लिए पर्याप्त धनराशि है। यदि एक साल की सब्सिडी साल भर की गरीबी मिटा सकती है तो 40 लाख करोड़ रूपए से 80 बर्षो की गरीबी मिटाई जा सकती है। फिर देश के राजनेता कोरपोरेट्स को दी जाने वाली सब्सिडी को उचित कैसे मान सकते हैं? अगर हम कोरपोरेट जगत को नजर में लाएँ तो बेरोज़गारी आसमान छू रही है। औद्यौगिक विकास व निर्यात की गति धींमी है। अगर इसे दिया जाने वाला प्रोत्साहन फायदा नहीं कर रहा है तो वह पैसा आखिर जा कहां रहा हैं?

दूसरी तरफ़ अमीर व्यक्ति बैंकों से पैसे लेता है और वापिस नहीं करते है। जिससे बैकों को एक आम आदमी का पैसा डूबत खाते में डालना पडता है। जिसकी वज़ह से बैकों का एन0पी0ए0 आज चिन्ताजनक हो गया है। वही यदि कोई गरीब व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और किसी कारणवश वापिस करने में देरी कर जाता है तो बैक उसकी संपत्ति जब्त कर लेता है। लेकिन कॉरपोरेट जगत आज भी दोनों हाथों से खाना चाहता है एक तरफ से लूट दूसरी तरफ से छूट। अर्थात लोग आज भी इन सब बातों से अनजान है।

बाल मजदूरी एक अभिशाप

शैलेश कौशल

भारत मे बाल मजदूरी एक बहुत बड़ी समस्या है जो नन्हें बच्चों से उनका बचपन छीन रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिससे इतनी कम उम्र के बच्चे काम करने पर मजबूर है। दूसरे देशों के मुकाबलें भारत में यह सख्यां काफी ज्यादा है। बच्चों से जबरदस्ती विना वेतन दिए कई घण्टें काम लिया जाता है। 2001 की जनगणना के मुताबिक बाल मजदूरों की सख्यां 11.28 मिलियन से बढ़कर 12.66 हो गई थी।

मुख्य रुप से छोटे कारखाने जिसमें सिगरेट, बीड़ी बनाने में 25 प्रतिशत बाल मज़दूर लगे है। इन्हें बनाने के साथ-साथ उन्हें इसके सेवन की भी लत लग जाती है। 5 से 14 बर्ष के बच्चो से मजदूरी करवाने में पहला स्थान सिक्किम (12.04) का आता है। इसके बाद राजस्थान (8.25) व ,हिमाचल प्रदेश (8.14) का है। गांवों में (12.9), शहरों (8.6)के मुक़ाबले बाल मजदूरों की संख्या है। माता-पिता गरीब होने के कारण आपनी जरुरतों को पूरा नही कर पाते है जिससे प्रायः बच्चे इस दलदल में धकेल दिए जाते हैं और उन्हें अपनी पढ़ाई से दूर होना पड़ता है।

गरीबी से मज़बूर बाल मजदूरी करता मासूम बच्चा। *साभार- इंटरनेट*

कुछ समय पहले बाल मज़दूरी पर कार्य करने हेतु भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला युसुफजई को संयुक्त रुप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस समस्या के निपटारे के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। सरकार ने 1986 में चाइल्ड एक्ट बनाया जिसके अन्तर्गत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया। लेकिन चाइल्ड एक्ट के 30 वर्ष होने के बावज़ूद भी यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कहीं न कहीं सरकार दवारा कार्य करने की रफ्तार भी धीमी नज़र आ रही है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को एकजुट होकर कार्य करना होगा तभी हम बच्चों के आने वाले उज्जवल भविष्य को बचा पाएगें।

जहां खुदा....

प्रथम पृष्ठ से खबर तथा इसका नाम खुदनेश्वर स्थान रखा गया अर्थात अनजान जहां खुदा एंव ईश्वर एक साथ निवास करते है। मान्यता यह है कि जब तक दोनों यानि कि शिवलिंग एंव मजार की पूजा साथ नही होगी तब तक आपकी मुरादें पूरी नही हो सकती।

थोड़ा सोचने की जरुरत है कि क्या ईश्वर,खुदा,ईसा-मसीह,वाहे-गुरु अलग-अलग है? क्या उनके वचन में कहीं एक धर्म से दूसरे धर्म में लड़ने की बात की कही गई है? धर्म जोड़ने की बात करता है जबकि कुछ लोग इसकी व्याख्या गलत तरीके से करके एक-दूसरे के प्रति असन्तोष फैला रहे है। साथ ही यह भारतीय संविधान में धर्म-निरपेक्षता शब्द को चरितार्थ करता है।

सफलता का राज 'प्रिया यादव' के साथ

संवाद संवादाता, टैब

प्रिया यादव पत्रकारिता एवं सृजनात्मक लेखन विभाग में अंतिम सत्र 2015-16 की छात्रा है। वह इस विभाग से पहली छात्रा है। जिन्होंने पहले ही प्रयास में 'नेट परीक्षा' उतीर्ण करने में सफलता हासिल की है।

हमारे संवादाता से अपने साक्षात्कार के दौरान कहा कि नेट परीक्षा में सफल होने के लिए 'बेसिक्स क्लियर' होना जरुरी है। साथ में उन्होंने बताया कि 18 घंटे की पढ़ाई नहीं बल्कि एकाग्र होकर की गयी रोजाना दो घंटे की पढ़ाई भी सफलता दिला सकती है।

पृष्ठ-सज्जा
नितिश पोजटा, ऋषिका शर्मा
संपादन
सुरिन्द्र ठाकुर, अंजना देवी
चित्र-संग्रह
नरेन्द्र शर्मा, सुरिन्द्र ठाकुर

संवाद टीम
अंजना देवी, मो. अर्सलान समदी, नरेन्द्र शर्मा, नितिश पोजटा, राजेश कुमार, शैलेश कौशल, ऋषिका शर्मा, सुरिन्द्र ठाकुर